Dainik Bhaskar

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 67 वर्षों में आयोजित की 1034 परीक्षाएं, 2.40 लाख का सिलेक्शन

जयपुर.लोकसेवा के क्षेत्र में सुयोग्य अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धा की कसौटी पर कस कर राज्य सरकार को योग्य और प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने में राजस्थान लोक सेवा आयोग की पहचान देश के अग्रणी संस्थाओं में बन रही है। सात दशक की दुरूह यात्रा में अनेक बाधाएं आई होंगी, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ लक्ष्य की ओर नजरें गड़ाए रखने की क्षमता के कारण इसने एक अभिनव संस्था के रूप में पहचान बनाई है।

पिछले तीन-चार वर्षों में आयोग के समक्ष प्रशासनिक चुनौतियां आई और इसकी छवि पर भी आंच आई। इस झंझावात से बाहर निकलने के लिए पिछले एक साल में भागीरथी प्रयास किए गए। आयोग का ध्येय वाक्य ऑनलाइन, ऑनटाइम रहा। एक जनवरी 2017 तक

आरपीएससी देश का सर्वश्रेष्ठ लोक सेवा आयोग बन जाएगा। इसके लिए टीम आरपीएससी कृत संकल्प है।

57 अभ्यर्थियों और 9 विषय विशेषज्ञ डिबार घोषित

आयोग के इतिहास में पहली बार परीक्षाओं के दौरान ब्लू टूथ तकनीकी या अन्य अवांछित साधनों के उपयोग के जरिए नकल करते पकड़े गए 57 अभ्यर्थियों को आयोग की सभी परीक्षाओं से डिबार (विवर्जित) किया गया। पेपर सेटिंग कार्य को सही तरीके से नहीं करने पर 9 विषय विशेषज्ञों को भी डिबार किया गया।

नवाचार के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2016 की उत्तर पुस्तिकाओं का अॉन स्क्रीन मार्किंग की नवीनतम तकनीकी से मूल्यांकन किया। इसके लिए 213 विषय विशेषज्ञों एवं प्रोफेसर को प्रशिक्षण दिया गया। इसके तहत 97,801 उत्तर पुस्तिकाओं के करीब 38 लाख पन्नों को स्कैन करके पासवर्ड से सुरक्षित रखते हुए विशेष तकनीक से प्रमाणित कुंजी के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया। यह देश में किसी भी आयोग का पहला प्रयास था। इस तकनीक के लिए आयोग को 29 जुलाई 2016 को स्मार्ट सिटी सम्मिट कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से नवाजा गया।

यह रही चुनौतियां और उनसे निपटने के उपाय

पिछले कुछ सालों में पेपर लीक, ब्लू टूथ या अन्य तकनीकी से नकल करना, वर्णनात्मक उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में अनियमितता, उत्तर कुंजी के विवाद, परीक्षा से संबंधित करीब 3 हजार ज्यादा प्रकरण कोर्ट में दायर होना, परीक्षाओं का समय पर नहीं होना जैसी चुनौतियां आयोग के सामने आई है। आयोग ने पेपर लीक जैसी समस्याओं से निपटने के लिए ऑनलाइन परीक्षा को बढ़ावा दिया है। ब्लू टूथ से नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने और प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थियों की जांच करने का काम किया। परिणाम में देरी रोकने के लिए ऑनस्क्रीन मार्किंग को अपनाया। परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर तैयार किया और 100% पालन किया गया।

पिछले एक साल में 84 ऑनलाइन परीक्षाएं भी आयोजित कराई

आयोग का गठन 20 अगस्त 1949 को हुआ था। पिछले 67 वर्षों मेंं 1034 परीक्षाएं आयोजित की हैं। इनके जरिए 2,40,193 अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया जा चुका है। पिछले एक वर्ष में आयोग ने 20,150 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। 84 परीक्षाएं ऑनलाइन और 5 परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित की गई। आगामी 31 दिसंबर 2016 तक 30,713 पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा।